2400 per person in rural areas and the poverty line of Rs 75·00 corresponding to calorie requirement of 2100 in urban areas

(2) These results are based on the provisional [illegible] NSS on household consumer expdr. of 32nd round (July 1977 to June 1978).

(3) The difference between the aggregate [illegible] expenditure estimated by Central Statistical Organisation [illegible] Accounts Statistics and that derived from the NSSO data has been prorata adjusted among the different States and Union Territories [illegible] information to allocate this difference among the States and Union Territories.

(4) The number of people below poverty line [illegible] March. 1978.

(5) For All India the number and percentage of people below the poverty line correspond to the population of the States included in the Statement.

Allocation of funds to Orissa under 'Minimum Needs Programme'

@1212. SHRI JAGADISH JAIN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what was the amount allocated to Orissa under 'Minimum Needs Programme' during 1981-82 and 1982-83;

(b) the amount spent by various departments of Orissa Government in those years out of the allocation made;

(c) whether Government propose allocation to Orissa for the above programme for 1983-84; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): a) and (b) The outlay and expenditure in the Plans of Orissa State under Minimum Needs Programme for the years 1981-82 and 1982-83 are given in the table below:—

(Rs. Lakhs)

Programme	1981-82		1982-83	
	Outlay	Actual Expdr.	Outlay	Anticipated Expenditure
Elementary Education	491	464	490	5[illegible]9
Adult Education	*	10	10	6
Rural Health	268	249	280	280
Rural Water Supply	600	592	665	665
Rural Electrification	350	350	434	434
Rural Roads	530	507	550	550
Rural Housing	50	50	57	57
Environmental Improvement of Urban Slums	15	15	15	15
Nutrition	75	75	70	75
TOTAL	2379	2312	2571	2591

@Previously unstarred Question 880 transferred from the 1st March, 1983.

*Included under Elementary Education.

(c) and (d). Yes, Sir. Details regarding the outlay under Minimum Needs Programme in the Annual Plan 1983-84 of Orissa State would be indicated in the Annual Plan Document which will be placed before Parliament as soon as possible after presentation of the State Budgets.

पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता

1213. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में जनता को जानकारी प्रदान करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) इस संबंध में प्रचार के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री विश्विजय सिंह) : (क) पर्यावरण विभाग विभिन्न अभियानों के द्वारा, सामान्य रूप से पर्यावरणीय जागरुकता का निर्माण करने के लिए और विशेष रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में चेतना जागृत करने के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहित करता रहा है । पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं, नियंत्रण उपायों और नीतियों पर प्रकाश डालते हुए, सूचनात्मक दृश्य-श्रव्य, फिल्में, पोस्टर, मुद्रित सामग्री, विशेष डाक टिकट, कलेण्डर आदि व्यापक रूप से परिचालित किये जा रहे हैं । पर्यावरणीय प्रदूषण से सम्बन्धित समाचार रिपोर्टों के विशेष अंक भी समय-समय पर जारी किए जाते हैं । जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने भी डाक्यूमेन्टरी फिल्में, दृष्य-श्रव्य कार्यक्रम, लोकप्रिय साहित्य, उद्योग विशेष फिल्में आदि जैसी अनेक लोक सूचना सामग्री प्रकाशित की हैं । प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा कानून का अनुपालन कराने में सहायता देने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए विशेष शिविरों का प्रबन्ध भी किया जाता है । पर्यावरण विभाग और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड भी पर्यावरणीय प्रदूषण को समर्पित संगोष्ठियों, परिसम्वादों और सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरुकता उपन्न करने का प्रयत्न करते हैं । ऐसे अभियानों का प्रयोजन पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करने में जनता का सहयोग प्राप्त करना है ।

(ख) प्रचार अभियानों को पुन: दोहराया जाना है और अत्यधिक जनता को अन्तर्ग्रस्त करने के लिए इनका विस्तार किया जाना है । आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, आदि जैसे सरकार में सम्बन्धित अभिकरणों का सहयोग भी संगत प्रचार सामग्री के उत्पादन और प्रसारण के लिए प्राप्त किया जाता है ।

---

12 NOON

RE INVITATION TO THE MEMBERS OF PARLIAMENT TO THE SEVENTH NON-ALIGNED CONFERENCE

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Sir, I would like to mention one thing. The Members of Parliament are being sidetracked in respect of the Non-Aligned Conference. It has always been the custom in other countries, wherever there has been the Non-Aligned Conference, that they will have tea with the Members of Parliament or at least the Members of the Opposition or the leaders of the Opposition have been called for tea with the delegates. Unfortunately, this procedure has been dropped by the present Government. I think, Sir, you should rectify the situation.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I am only supporting Mr. Kalmadi. Mr. Mukherjee, are you saying something on this? (*Interruptions*).